

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-32
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के तहत संस्थानों की स्थापना

32. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत छह वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार और बिहार राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम या केंद्र प्रायोजित पहल के तहत बिहार में स्थापित नए शैक्षणिक संस्थानों (जैसे विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, तकनीकी संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) का व्यौरा क्या है;
- (ख) संस्थानों का व्यौरा क्या है जिसमें उनकी श्रेणी/स्थिति (सरकारी/सहकारी/निजी), स्थापना वर्ष, स्थान और उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता शामिल है; और
- (ग) उपरोक्त संस्थानों की वर्तमान कार्यक्षमता और वर्तमान छात्रों, शुरू किए गए पाठ्यक्रमों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) कक्षाओं और प्रयोगशालाओं आदि का व्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-यूएसएचए) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तृतीय चरण का शुभारंभ किया है, जिसमें आरयूएसए के पूर्व चरण की प्रतिबद्ध देयताएं भी शामिल हैं।

पीएम-यूएसएचए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन जिलों में कोई सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्था नहीं है, वे नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एनएमडीसी) की स्थापना के लिए पात्र हैं। विंगत 6 वर्षों (अर्थात वर्ष 2019 से 2024 तक) के दौरान बिहार में किसी भी एनएमडीसी को मंजूरी नहीं दी गई है।

तथापि, रूसा 2.0 के तहत, बिहार में 2018 में अररिया, कटिहार, पूर्णिया और गया जिलों में नए मॉडल डिग्री कॉलेज घटक के तहत प्रत्येक के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि के साथ चार नए मॉडल डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। आज की स्थिति के अनुसार, एनडीएमसी पूर्णिया का कार्य पूर्ण हो चुका है।
